Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to focus on research and production of coarse grains and bring them under Public Distribution System.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) ः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों की आमदनी को आने वाले समय में दोगुना करने का संकल्प लिया है और यह संकल्प दूसरी हरित क्रांति के माध्यम से होगा। पहली हरित क्रांति में हमारा ध्यान केवल मात्र गेहूँ व धान की खेती पर था। बाकी परंपरागत फसलें गौण हो गई थीं। अब वक्त के साथ देश में मोटे अनाजों के महत्व को समझा गया है, इससे न केवल किसानों को मुफलिसी दूर होगी, बल्कि देश की जनता के स्वास्थ्य में भी क्रांतिकारी परिणाम देखने को मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाए गए 17 गोल्स में से तीसरा लक्ष्य स्वास्थ्य संबंधी ही है, जिसमें देश की जनता के लिए हेल्दी फूड की आवश्यकता महसूस की गई है। आज विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय शोध भी मोटे अनाजों की पौष्टिकता प्रमाणित कर रहे हैं। मोटे अनाजों की खेती पर्यावरण को नुकसान नहीं करती क्योंकि इन फसलों में कम पानी, कम रासायनिक उर्वरक और कम कीटनाशकों की जरूरत पड़ती है। मोटा अनाज पोषक तत्वों का खजाना हैं, जैसे कि काबुली चने में 23 प्रतिशत प्रोटीन होते हैं। चावल की तुलना में कंगनी में 81 प्रतिशत अधिक पौष्टिक तत्व होते हैं। सावां में 840 फीसदी ज्यादा फैट, 350 प्रतिशत फाइबर, 1229 प्रतिशत आयरन होता है। बाजरा में 85 प्रतिशत अधिक फास्फोरस होता है, जबकि रागी में 340 फीसद अधिक कैल्शियम होता है।

अतः मैं कृषि मंत्री से माँग करता हूँ कि मोटे अनाजों का भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण किया जाए। मोटे अनाजों का समर्थन मूल्य भी घोषित हो। मोटे अनाजों की उपज को बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास सुविधाएं स्थापित हों। मोटे अनाज की खेती के लिए रियायती दर पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। सरकारी सब्सिडी नीति की दिशा मोटे अनाजो की पैदावार की ओर बढ़ेगी तो देश में पौष्टिकता से लबालब ये मोटे मनाज हमारे देश के स्वास्थ्य इंडेक्स को अच्छे स्तर पर बढ़ाने में कामयाब होंगे।